



The
ACHIEVERS IAS ACADEMY

A Serious & Genuine Institute For UPSC & BPSC

**DAILY CURRENT AFFAIRS
For UPSC/BPSC**

DATE : 23-07-2024

NOTE : Collect FREE copy of Monthly Current Affairs Magazine From our Centre



+91-84349 31877, +91-72506 67974



www.achieversiaspatna.co.in



achieversiaspatna@gmail.com



Orchid Mall, Boring Road (Opp: A.N. College) Patna 800001

इस साल अर्थव्यवस्था में 7% की वृद्धि होने की संभावना: सर्वेक्षण

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 पेश किया।

मुख्य आर्थिक सलाहकार (सीईए) वी. अनंत नहेश्वरन ने आर्थिक सर्वेक्षण में चर्चा किए गए कुछ प्रमुख मुद्दों पर बात की।

पहले अध्याय "अर्थव्यवस्था की स्थिति" में चर्चा किए गए कुछ प्रमुख बिंदु हैं:

- इस साल अर्थव्यवस्था में 6.5 से 7% की वृद्धि होने की संभावना है, आने वाले वर्षों में 7% से अधिक की वृद्धि की संभावना है।
- सर्वेक्षण में केंद्र और राज्यों से व्यवसायों पर बोझ कम करने के लिए अपनी असंख्य राज्य शक्तियों का उपयोग करने और अपनी असंख्य नियामक शक्तियों को छोड़ने का आह्वान किया गया है।
- सीईए ने भारतीय उद्योग से यह सोचने का आग्रह किया कि वह श्रमिकों को विस्थापित करने के बजाय श्रम को कैसे बढ़ा सकता है।
- भारत महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास की ओर बढ़ रहा है। महिला श्रम शक्ति की भागीदारी बढ़ रही है।
- मनरेगा योजना के तहत मांग आर्थिक संकट का वास्तविक संकेतक नहीं थी।

आर्थिक सर्वेक्षण वित्त मंत्रालय द्वारा तैयार किया गया एक दस्तावेज है, और बजट पेश होने से एक दिन पहले जारी किया जाता है।

इस दस्तावेज में अर्थव्यवस्था के प्रदर्शन के बारे में जानकारी होती है। इसमें भविष्य की नीति के लिए महत्वपूर्ण जानकारी शामिल होती है।

Going strong, concerns remain

While the 2024 Economic Survey said the economy is resilient, it warned about widening inequality and the need to add lakhs of jobs annually

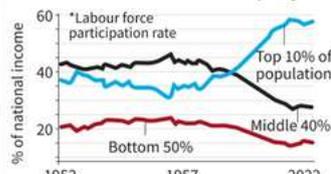
Consistent growth

Real GDP grew by 8.2% in FY24, posting growth in excess of 7% for a third year



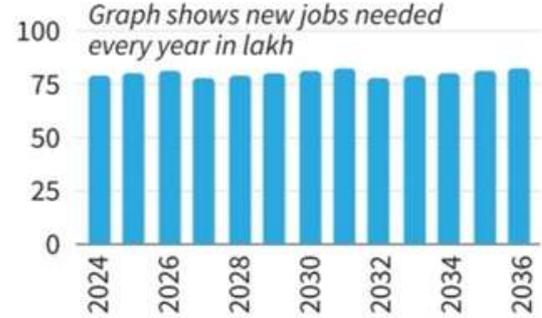
Widening inequality

Informal sector integration and expansion of female LFPR* in focus to address inequality



Quantum of new jobs needed

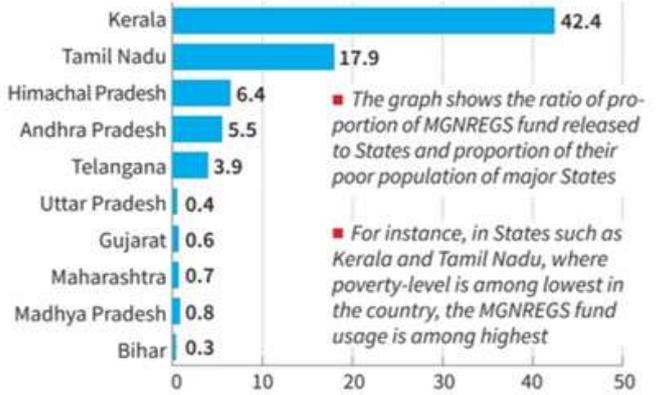
India needs to generate nearly 78.5 lakh jobs annually until 2030 in the non-farm sector to cater to the rising workforce



Source: Economic survey, World Inequality Lab

A closer look

According to the Economic Survey, MGNREGS fund usage does not indicate the poverty-level of a State



सुप्रीम कोर्ट ने कांवड़ यात्रा मार्ग पर स्टॉल पर मालिकों के नाम प्रदर्शित करने के आदेश पर रोक लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार द्वारा जारी किए गए प्रवर्तन निर्देशों पर रोक लगा दी, जिसके तहत कांवड़ यात्रा के मार्ग पर स्थित दुकानों और खाद्य स्टॉलों को मालिक और उनके कर्मचारियों का नाम और पहचान प्रदर्शित करना अनिवार्य किया गया था।

जस्टिस हृषिकेश एन रॉय और जस्टिस एसवीएन भट्टी की पीठ ने कहा कि कांवड़ यात्रा मार्ग पर स्थित स्टॉल, ढाबा, सब्जी विक्रेता, फेरीवाले आदि को उनके मालिकों और कर्मचारियों का नाम या धार्मिक पहचान या जाति पहचान दिखाने के लिए बाध्य नहीं किया जाना चाहिए।



याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि यह निर्देश राष्ट्र के धर्मनिरपेक्ष चरित्र को प्रभावित करता है और समानता, जातिगत भेदभाव न करने और जीवन की गरिमा के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है।

सुप्रीम कोर्ट ने आईआईटी दिल्ली के विशेषज्ञों को नीट भौतिकी के पेपर से 'अस्पष्ट' प्रश्न हल करने का निर्देश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के निदेशक को नीट यूजी 2024 के पेपर से एक पेचीदा "अस्पष्ट" समस्या को हल करने के लिए तीन सदस्यीय पैनल बनाने को कहा।

इस प्रश्न का एक सही उत्तर पुरानी एनसीईआरटी पुस्तक पर आधारित है और दूसरा नई एनसीईआरटी पुस्तक पर आधारित है। एनटीए ने दोनों उत्तरों को पूरे अंक दिए हैं।

याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि दोनों उत्तर एक साथ सही नहीं हो सकते।

बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने से केंद्र के इनकार के बाद लालू ने कहा कि नीतीश को इस्तीफा दे देना चाहिए

वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने संसद में जेडी(यू) सांसद रामप्रीत मंडल को लिखित जवाब में कहा, "बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने का मामला नहीं बनता है"।

जवाब में कहा गया कि बिहार राज्य के विशेष दर्जे के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद (एनडीसी) के मानदंडों को पूरा नहीं करता है।

एनडीए की बैठक में सीएम नीतीश कुमार ने हालांकि कहा कि केंद्र ने "कुछ अच्छा देने का वादा किया था"।

आरजेडी और प्रदेश कांग्रेस ने इस मामले में नीतीश कुमार के इस्तीफे की मांग की है।

सरकारी कर्मचारियों को आरएसएस में शामिल होने की अनुमति देना बीजेपी और मातृसत्ता के बीच संबंधों में सुधार का संकेत है

सरकार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) में शामिल होने वाले सरकारी कर्मचारियों पर प्रतिबंध हटा दिया है।

यह कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के 9 जुलाई के आदेश के साथ आया है।

विपक्ष ने सरकार की आलोचना की है। जबकि आरएसएस ने भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए इसकी प्रशंसा की है।

1966 में इंदिरा गांधी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के आरएसएस में शामिल होने पर प्रतिबंध लगाया था।

जनसंघ आरएसएस द्वारा गोहत्या विरोधी प्रदर्शन पर पुलिस की गोलीबारी में कई लोगों की मौत के बाद यह प्रतिबंध लगाया गया था।

विश्व : _____

हैरिस ने जो बिडेन की बेजोड़ विरासत की सराहना की, क्योंकि पार्टी ने समर्थन बढ़ाया

अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने पहली बार जो बिडेन की "बेजोड़" विरासत की सराहना की, जो बिडेन द्वारा राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में समर्थन दिए जाने के बाद पहली बार सार्वजनिक रूप से सामने आई।

"पिछले तीन वर्षों में जो बिडेन की विरासत की उपलब्धि आधुनिक इतिहास में बेजोड़ है।" सुश्री हैरिस ने कहा।

मिशिगन की गवर्नर ग्रेचेन और पूर्व हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी सहित कई डेमोक्रेट ने उनकी बोली का समर्थन किया है।

बांग्लादेशी छात्र समूह ने 48 घंटे के लिए विरोध प्रदर्शन स्थगित किया

सोमवार को प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे बांग्लादेशी छात्र समूह ने 48 घंटे के लिए विरोध प्रदर्शन रोक दिया।

इसके नेता ने कहा कि वे इतने खून-खराबे के साथ सुधार नहीं चाहते थे।

सैनिकों के सड़कों पर मार्च करने के साथ कर्फ्यू लगा दिया गया है।

यूएई ने विरोध प्रदर्शन के लिए 53 बांग्लादेशी नागरिकों को जेल में डाला

यूएई की एक अदालत ने 53 बांग्लादेशियों को जेल की सजा सुनाई। जिसमें तीन को आजीवन कारावास भी शामिल है।

बांग्लादेशियों को अपने देश के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के लिए गिरफ्तार किया गया था।

शनिवार को अधिकारियों ने अप्रत्याशित सुनवाई का आदेश दिया।



इथियोपिया में भूखलन में कम से कम 55 लोगों की मौत

सोमवार को दक्षिणी इथियोपिया के एक दूरदराज के इलाके में भूखलन में कम से कम 55 लोगों की मौत हो गई, अधिकारियों ने चेतावनी दी कि मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है।

भारी बारिश के कारण भूखलन हुआ।
हताहतों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं।

इजरायली सेना ने गाजा मानवीय क्षेत्र के एक हिस्से से लोगों को निकालने का प्रस्ताव दिया

इजरायली सेना ने सोमवार को मवावासी मानवीय क्षेत्र से लोगों को निकालने का आदेश दिया।

सेना ने कहा कि वह इस क्षेत्र में हमला करने जा रही है।

हमला शुरू करने से पहले नागरिकों को राफा से निकालने के लिए इस क्षेत्र का निर्माण किया गया था।

इस महीने की शुरुआत में इजरायल ने अनुमान लगाया था कि मानवीय क्षेत्रों में करीब 1.8 मिलियन लोग रह रहे हैं।

यह 2.3 मिलियन आबादी का बड़ा हिस्सा है।

संपादकीय : _____

डेमोक्रेटिक प्रस्थान

बाइडेन के दौड़ से हटने से राष्ट्रपति चुनाव का रास्ता खुल सकता है

संपादकीय में डोनाल्ड ट्रंप के डेमोक्रेट्स की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी से हटने के बारे में बताया गया है। उन्होंने उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के नाम का समर्थन किया है।

डोनाल्ड ट्रंप के साथ बहस में अपेक्षाकृत खराब प्रदर्शन के बाद डेमोक्रेटिक साथियों के दबाव के बाद श्री बाइडेन ने यह फैसला लिया है।

कमला हैरिस इस सीट के लिए चुनाव लड़ने वाली पहली भारतीय और अश्वेत महिला होंगी।

संपादकीय में कहा गया है कि चुनाव में केवल चार महीने बचे हैं। ट्रंप के कमला हैरिस को हराने की संभावना अधिक है।

कोटा की तलाश

बांग्लादेश को अपने बढ़ते बेरोजगारी संकट का समाधान करने की जरूरत है

संपादकीय हाल के विरोध प्रदर्शनों और रविवार को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बारे में है।

प्रदर्शनकारी बांग्लादेश की आजादी में लड़ने वाले दिग्गजों के बच्चों के लिए 30% कोटा का विरोध कर रहे थे। सीटों का कुल आरक्षण 56% था।

इसके चलते छात्रों ने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया। आरक्षण के पक्ष में और इसके विरोध में कई जगहों पर झड़पें हुईं। विपक्ष ने भी इस विरोध का समर्थन किया।

प्रधानमंत्री शेख हसीना ने प्रदर्शनकारियों को रजाकार कहा, यह उनकी सबसे बड़ी गलतियों में से एक थी।

रजाकार वे लोग हैं जिन्होंने बांग्लादेश नरसंहार में पाकिस्तानी सेना की मदद की थी। बांग्लादेश सेना की मनमानी की कड़ी आलोचना की गई है।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश ने आरक्षण को घटाकर 7% कर दिया है। युद्ध के दिग्गजों के बच्चों के लिए 5%। अब 93% सीटें गैर आरक्षित हैं



The
ACHIEVERS
IAS ACADEMY

NEW BATCH FOR
UPSC
FOUNDATION & TARGET
IN PATNA

STARTING FROM
1ST AUG 2024

ADMISSION
OPEN

Patliputra Colony, Near H.N. 181, Tennis Court, Patna - 800013
CALL : +91-84349 31877, +91-72506 67974

